



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 14, 1990/फाल्गुन 23, 1911

No. 61] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 14, 1990/PHALGUNA 23, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दो जाते हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

### वार्षिक भंत्रालय

(नियमित व्यापार नियमण)

सार्वजनिक सूचना सं. 15/ई.टी.सी. (पी.एन.)/90

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1990

विषय— 1 जनवरी, 1988 में 31 दिसंबर, 1990 तक खुले  
सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत संयुक्त भूराज्य अमेरिका,  
यूरोपीय अर्थिक समूदाय मदस्य राज्यों, आस्ट्रिया,  
फ़िल्लैंड, स्वीडन, नार्वे और कनाडा को गरमेंट्स और  
नियन्त्रित हेतु स्कीम।

फ़ा.स. 2/19/88 ई. 1.—उपर्युक्त विषयक 15 अक्टूबर, 1987  
की सार्वजनिक सूचना सं. 28-ई.टी.सी. (पी.एन.)/87 और वाद के  
संशोधनों की ओर ध्यान आर्कषित किया जाता है। यह निर्णय किया  
गया है कि सार्वजनिक सूचना को आगे निम्न प्रकार से संशोधित किया  
जाए:—

2. पैरा 6 के उन पैरा (5)(क) को हटा दिया जाए।

3. पैरा 6 के उन पैरा 5(व) को निम्नोक्त द्वारा प्रतिस्थापित  
किया जाए:—

6(5) (ब) अन्तर्राती को अन्तर्रात माला के नियान्त हेतु सम्बद्ध  
अवधि जिसमें अन्तरण प्रभावी हुआ है की समाप्ति  
से 30 दिन का समय अनुमत्य होगा। 30 मित्रस्वर  
के उपरान्त 31 दिसंबर तक पोतलदान के लिए  
दूसरी अवधि के लिए अन्तरित हकदारियों की  
अनुमति मालूम पत्र द्वारा अनुसमर्थित विषेष सविदाओं के  
महे जहज पर्यात नियमित मूल्य के 20% की  
दर से जमा पेशी राशि/बैक गारन्टी प्रस्तृत करने के  
अध्ययन दो जाएगी।"

4. पैरा 8(3) को निम्नोक्त द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

"8(3) इस सिस्टम के अन्तर्गत आबंटन सम्बन्धित आबंटन अवधि  
के अन्त तक वैध होगा अर्थात् आबंटन 1 अप्रैल से आगे  
किया जाएगा जो कि 30 जून तक वैध होगा। 1 अगस्त से आगे  
किए गए दूसरी अवधि के आबंटन 30 अक्टूबर  
तक वैध होंगे। 1 अक्टूबर, से आगे किए गए आबंटन  
31 दिसंबर तक वैध होंगे।

5. परा 11 के उप परा (4) में शब्द "25 देश/श्रेणियाँ" को "15 देश/श्रेणियों" वाले प्रतिस्थापित किया जाए।

6. परा 16 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएः—

16. नियंत्रित हक्कदारी के प्रमाणन की वैध अवधि:—

भूतकालीन नियादन हक्कदारी/पैन-कोडा हक्कदारी/विनियोगी नियंत्रित हक्कदारी और केन्द्र/राज्य नियम प्रिट्स के मामलों में पोतलदान बिलों के मध्यें में प्रमाणन 30 दिन की अवधि के लिए वध होगा।

वर्गीकृत आवंटन कोनसो पट्टों में वैश्वा का विवराधान हक्कदारी को सूल अवधि का नियम से अधिकार 30 दिनों की अवधि के लिए वर्डान जाता है, लेकिन 31 दिसंबर, के पश्चात नहीं वह इस जारी के अंतर्गत होता है। कि नियंत्रित जहज-नियम नियंत्रित हक्कदारी के लिए वर्डान जाता है। वैश्वा का विवराधान सूल अवधि का नियम से 60 दिनों की अवधि के लिए वर्डान जाता है, लेकिन 31 दिसंबर के पश्चात नहीं, वह इस जारी पर कि नियंत्रित जहज-पर्मत्र नियंत्रित हक्कदारी के प्रमाणन का वैश्वा अवधि के लिए वर्डान के लिए नहीं।

वैश्वा देने के लिए अर्थवा एक्सपोर्ट प्रान्तों का उत्तित सम्म होती है। ऊपर दिए गए के अनुसार, छाटों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। प्राकृतिक आवंटन वैश्वा की दरकार जारी जाएं तो केवल ईएमडी/ओ जो को जटी के प्रमोन के लिए विवरणों दोंगो नियंत्रित हक्कदारी के प्रमाणन का वैश्वा अवधि के लिए वर्डान के लिए नहीं।

7. भारत-रा. परा यांत्रिक 15 अक्टूबर, 1987 को सार्वजनिक सूचना सं. 28-E.T.C. (PN)./87 द्वारा अधिसूचित स्कोर के समान अन्वे उत्तरव्य लिया गया।

तेजेन्द्र खाना,  
मुख्य विवक्षक, आवान नियन

#### MINISTRY OF COMMERCE

(EXPORT TRADE CONTROL)

PUBLIC NOTICE NO. 15-ETC (PN) /90

New Delhi, the 14th March, 1990

Subject :—Scheme for export order CGL 3 of garments and knitwear to USA, EEC Member States Austria, Finland, Sweden, Norway and Canada from 1st January, 1988 to 31st December, 1990.

File No. 2/19/88-E-I.—Attention is invited to Public Notice No. 28-ETC (PN)/87, dated the 15th October, 1987 and subsequent amendments on the above subject. It has been decided to further amend the Public Notice as following :—

2. Sub-para (v) (a) of para 6 is deleted.

3. Sub-para (v) (b) of para 6 is substituted by the following :—

"6(v)(b) A transferee would be allowed 30 days from the end of the relevant period, in which transfer is effected, to export the transferred quantity. Transferred entitlements of the 2nd period would be permitted for shipment beyond 30th September upto 31st December against specific contracts backed by Letter of Credit subject to submission of Earnest Money Deposit/Bank Guarantee at the rate of 20 per cent of FOB value."

4. Para 8(iii) is substituted by the following :—

"8(iii) Allotments under this System will be valid upto the end of the relevant allotment period, i.e. allotments to be made from 1st April onwards will be valid upto 30th June. The second period allotments made from 1st August onwards will be valid upto 30th October. Allotments to be made from 1st October onwards will be valid upto 31st December."

5. In sub para (iv) of para 11 the words "25 countries/categories" are substituted by the words "15 countries/categories."

6. Para 16 is submitted by the following :—

**"16. Validity Period of Certification of Export Entitlement :—**

A certification on the shipping bills shall be valid for a period of 30 days in the case of P.M. Performance Entitlement/Non-quota Entitlement/Manufacturer Exporters Entitlement and Central/State Corporations Systems.

Provided that in all systems of allotment validity can be extended for a maximum period of 30 days from the original expiry of the entitlement in question, but not beyond 31st December, subject to the exporter submitting a net additional Bank Guarantee of 15 per cent of FOB value. Validity can be further extended by another 30 days, but not beyond 31st December subject to the exporter submitting a net additional bank guarantee of 10 per cent of FOB value. In other words, in all systems of allotment, validity can be extended for a maximum period of 60 days from the original expiry of the entitlement in question, but not beyond 31st December, subject to the exporters submitting a net additional Bank Guarantee of 25 per cent of FOB value. The Appeal Export Promotion Council shall be competent to grant the extensions. There shall be no extension of quotas except as provided above. If force majeure conditions, where they arise, shall be considered for the purpose of forfeiture of EID Bank Guarantee, and not for the purpose of extension of validity period of Certification of Export Entitlements."

7. All other provisions of the Scheme notified in Public Notice No. 28-ETC(PN)/87 dated the 15th October, 1987, as amended from time to time, remain unchanged.

TEJENDRA KHANNA, Chief  
Controller of Imports & Exports.